two members. Thereafter, with the co-option of three more members and publication of the names of all the members in the Gazette, the new Haj Committee will be in place.

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

Cold Storage plans in Assam

2439. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the specific reasons for not establishing any cold storage plants for agriculture and horticulture produce in Assam during the last five decades;

(b) whether Government propose to set up cold storage plants for the said purpose in the State during the Ninth Five Year Plan;

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(d) whether Government have made a detailed survey to find out the number, location, capacity and specific pattern required for setting up of such plants in the State; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL) : (a) to (c) The National Cooperative Development Corporation (NCDC) provides loan assistance to the cooperatives through the State Governments to set up cold storage in the country, So far, NCDC has assisted one cold storage unit of 1000 tonne capacity in Guawahati during the year 1968-69. However, State Cooperative Marketing Federation could not operate it successfully and, therefore, the unit was ultimately closed. NCDC has not received any other proposal from the State Government of Assam for setting up of cold storage in the cooperative sector. The National Horticulture Board (NHB) is providing financial assistance in the form of soft loan at the rate of 4% service charges for establishment of cold storages by Cooperative Societies, MGOs, Agribusiness Consortium, State Agro/Horticulture Corporations and Companies. The NHB did not receive any proposal from any organisation for establishment of cold storage in Assam upto 31st March, 1997. However, NHB has recently received a proposal from M/s Boruah and Company Ltd. for financial assistance to the extent of Rs. 35.00 lakhs for establishment of post-harvest management-cum-cold storage centre near Guwahati. The proposal has been examined and certain additional information has been sought from the company. It is the intention of the NHB to accord priority to proposals received from the North Eastern Region during the 9th Plan period.

(d) and (e) Such surveys are undertaken by the State Governments. NCDC and NHB consider proposals for assistance to cold storages as and when these are duly recommended by the concerned State Governments.

खाद्यान्नों और दलहनों का उत्पादन

2440. श्री जनेश्वर मिश्र: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष खाद्यान्नों का कुल उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दलहनों और तिलहनों के उत्पादन में भी कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) से (घ) 1996-97 की तुलना में 1997-98 के दौरान खाद्यान्नों, दलहनों तथा तिलहनों का उत्पादन कुछ कम हुआ है। राज्य-वार ब्यौरे का विवरण संलग्न है (नीचे देखिये)

विवरण

1996-97 और 1997-98 के दौरान खाद्यान्न, दलहन तथा तिलहनों के उत्पादन का राज्य-वार अनुमान उत्पादन (हजार टन)

राज्य	खाद्यान्न		दलहन		तिलहन	
	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98
आंध्र प्रदेश	12684	10421	768	562	2420	1447
असम	3532	3804	68	73	155	172
बिहार	14134	13289	613	666	161	143
गुजरात	5209	5700	663	781	3809	4056
हरियाणा	11455	10980	343	440	1004	866
हिमाचल प्रदेश	1289	1409	11	33	10	11
जम्मू व कश्मीर	1324	1644	17	22	44	42
कर्नाटक	9271	8638	669	485	1714	1380
केरल	858	1151	15	19	11	17
मध्य प्रदेश	19563	18813	3715	3376	1998	6041
महाराष्ट्र	14590	10172	2037	1381	2384	1971
उड़ीसा	4834	6871	299	384	177	180
पंजाब	21564	21649	81	97	310	303
राजस्थान	12838	12925	1876	1908	3525	3222
तमिलनाडु	7645	8761	410	391	1929	1468
उत्तर प्रदेश	42693	42001	2664	2231	1772	1668
पश्चिम बंगाल	13739	13803	156	173	451	619
अन्य	2099	2096	54	53	82	83
समस्त भारत	199321	194127	14460	13075	24960	23689

गन्ना उत्पादक क्षेत्र

2441. **श्री रामगोपाल यादव:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन प्रदेशों में गन्ने का उत्पादन अधिक होता है;

(ख) इन राज्यों में गन्ना उत्पादक क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है;

(ग) क्या गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहित करने और समय पर गन्ने की पिराई को सुनिश्चित करने के लिए उक्त राज्यों में गन्ना मिलों की स्थापना करने हेतु सुविधाएं प्रदान की जाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) वर्ष 1997-98 के दौरान मुख्य गन्ना उत्पादक राज्यों में गन्ने के क्षेत्र को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है **(नीचे देखिये)**।

(ग) और (घ) चीनी के नए कारखानों को लाइसेंस प्रदान करने और विद्यमान चीनी कारखानों के विस्तार संबंधी दिशा निर्देशों में प्रति दिवस न्यूनतम पिराई क्षमता, मिलों द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकियों के अपनाने, प्रस्तावित और विद्यमान गन्ना मिलों के बीच रखी जाने वाली कम से कम दूरी, ईख (गन्ना) की उपलब्धता और/अथवा क्षेत्र में गन्ने के विकास की सम्भावना, उत्पादक सहकारी समितियों को तरजीह आदि का ध्यान रखा जाता है। इन उपायों से गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलेगा और गन्ने की समय पर पिराई सुनिश्चित होगी।